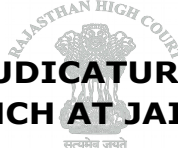




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 279/2026

Rajesh Kumar S/o Vishambhar, R/o Rudaval, Police Station
Rudaval, District Bharatpur.

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor.
2. The Director General Of Police, Rajasthan, Jaipur.
3. The Superintendent Of Police, Bharatpur.
4. The Station House Officer, Police Station Rudaval, District
Bharatpur.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Himmat Singh Bikaarwar, Adv.
For Respondent(s)	:	Ms. Manju Dave, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

20/04/2026

विद्वान अधिवक्ता याची-परिवादी का निवेदन है कि विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 29.11.2025 में दिये गये निर्देशों के बावजूद पुलिस द्वारा विवादित दस्तावेज की एफ.एस.एल. जांच नहीं करायी गयी है, अतः इस संबंध में उचित आदेश दिये जावें।

आदेश दिनांक 29.11.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया है कि यदि अनुसंधान अधिकारी आवश्यक समझे तो एफ.एस.एल. से दस्तावेज की जांच करावे, किन्तु कोई स्पष्ट आदेश नहीं है।

अनुसंधान किस रूप में किया जावे, इस बाबत कोई भी न्यायालय विशिष्ट निर्देश देने हेतु अधिकृत नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अनुसंधान हो यह सुनिश्चित करने हेतु संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय अधिकृत है।



माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत Sakiri Vasu Vs. State of U.P. & Ors. AIR 2008 SC 907 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निष्पक्ष अनुसंधान को सुनिश्चित करने हेतु संबंधित मजिस्ट्रेट न्यायालय अनुसंधान को मोनिटर करने व आवश्यक निर्देश देने हेतु सक्षम है तथा ऐसे मामलों में सामान्य रूप से धारा 528 बी.एन.एस.एस./482 दण्ड प्रक्रिया संहिता की शक्तियों का प्रयोग किया जाना उचित नहीं है तथा ऐसी प्रवृत्ति निरुत्साहित होने योग्य है। इस निर्णय के पैरा संख्या 15 व 25 सुसंगत हैं जो निम्नानुसार है—

"15. Section 156(3) provides for a check by the Magistrate on the police performing its duties under Chapter XII Cr.P.C. In cases where the Magistrate finds that the police has not done its duty of investigating the case at all, or has not done it satisfactorily, he can issue a direction to the police to do the investigation properly, and can monitor the same.

25. We have elaborated on the above matter because we often find that when someone has a grievance that his FIR has not been registered at the police station and/or a proper investigation is not being done by the police, he rushes to the High Court to file a writ petition or a petition under Section 482 Cr.P.C. We are of the opinion that the High Court should not encourage this practice and should ordinarily refuse to interfere in such matters, and relegate the petitioner to his alternating remedy, firstly under Section 154(3) and Section 36 Cr.P.C. before the concerned police officers, and if that is of no avail, by approaching the concerned Magistrate under Section 156(3)."

उपरोक्त विधिक व्यवस्था आदि को देखते हुए याची-परिवादी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह संबंधित मजिस्ट्रेट/न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने हेतु आवेदन पेश कर सकता है। इसी टिप्पणी के साथ यह याचिका निस्तारित की जाती है।

(UMA SHANKER VYAS),J